(viii) Rewards are given to informers for gathering intelligence regarding illegal trade and smuggling of wildlife products.

(ix) A Committee set up by this Ministry to look into issues related to illegal trade in wildlife and wildlife products has recommended specific measures to deal with this problem and these are being followed up with the States for implementation.

(x) Regional and sub-regional offices of Wildlife Preservation have been set up mainly at the major export centres of the country to prevent illegal trade and smuggling of wildlife products.

राष्ट्रीय महिला कोष से लाभान्वित महिलाएं

***147. श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994 के दौरान और अब तक प्रत्येक वर्ष के अनुसार गुजरात के प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय महिला कोष से कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं और कितने महिला संगठनों को ऋण दिये गये।

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान और अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए आगामी वर्षों में कोष के क्रियाकलापों को बढ़ाने हेतु सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई): (क) राष्ट्रीय महिला कोष को 1993-94 में गुजरात से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। 1994-95 में पांच गैर-सरकारी संगठनों से आवेदन किया, जिनमें से तीन संगठन कोष द्वारा निर्धारित मापदण्ड को पूरा नहीं करते थे। दो गैर-सरकारी संगठनों को ऋण दिया गया, जो 570 लाभार्थियों के लिए था। 1995-96 में, एक गैर-सरकारी संगठन, जिसने आवेदन किया था, को 25 स्व-सहायता दल बनाने के लिए ऋण दिया गया। 1996-97 में अब तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग): राष्ट्रीय महिला कोष का मुख्य बल इसकी पहुंच को बढ़ाना है, ताकि इसके अन्तर्गत कम औपचारिक ऋण प्रणाली का लाभ यथासम्भव कम अवधि में अधिकतम लाभार्थियों को पंहुचाया जा सके। चूंकि, ऋण देने में राष्ट्रीय महिला कोष की मुख्य कठिनाई ऋण प्रबन्धन में अनुभवी गैर-सरकारी संगठनों की कमी है, इसलिए ऋण प्रबन्धन कौशल में गैर-सरकारी संगठनों को प्रशिक्षित करने और बड़े अनुभवी गैर-सरकारी संगठनों को ऋण प्रदान करके छोटे कम अनुभवी संगठनों को आगे ऋण देने की अनुमति प्रदान करने की नई स्कीमें शुरू की गई हैं। इस प्रकार छोटे कम अनुभवी संगठन भी प्रशिक्षित हो जाएगें। ये संवर्धनात्मक स्कीमें हैं:-

(1) संसाधन गैर-सरकारी संगठन स्कीम:-इसका उद्देश्य अनुभवी गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से छोटे संगठनों के प्रशिक्षण का विधियन करना है। इस स्कीम के अन्तर्गत प्रशिक्षित संगठन ऋण और बचत प्रबन्धन में 3 वर्ष के अनुभव के बिना राष्ट्रीय महिला कोष से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

(2) छत्र स्कीम:-बचत और ऋण में अपेक्षित अनुभव से कम अनुभव वाले छोटे गैर-सरकारी संगठन जिन्होंने अन्य क्षेत्रों में कार्य किया हो, छात्र गैर-सरकारी संगठन की सिफारिश पर राष्ट्रीय महिला कोष के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

(3) नोडल एजेंसी स्कीम:- कोष की पहुंच बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय महिला कोष ने चुनिन्दा राज्य स्तरीय महिला विकास निगमों, इन्दिरा महिला ब्लाक समितियों और गैर-सरकारी संगठनों को आगे ऋण देने और मार्ग दर्शन करने संबंधी कार्यकलापों में शामिल करने का निर्णय लिया है।

(4) जागरूकता शिविर:-इसके अन्तर्गत महिलाओं के लिए जागृति विकास शिविर आयोजित करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को राशि प्रदान की जाती है, जो अन्य बातों के अलावा, आत्मानिर्भरता और आर्थिक स्वतन्त्रता के एक साधन के रूप में बचत के महत्व को उजागार करते हैं।

Vehicles without Catalytic Converters

*148. SHRI MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the number of already registered vehicles in four metropolitan cities which do not and

cannot be fitted with catalytic converters for using unleaded petrol; and

(b) the measures proposed to be taken by Government to minimise pollution levels of the existing licenced old vehicles?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (CAPTAIN JAIN NARAYAN PRASAD NISHAD): (a) The total number of registered 4-wheeler petrol vehicles in the four major metropolitan cities of Delhi, Mumbai, Calcutta and Madras as on 1.4.1995 is given below:

METRO	TOTAL NUMBER
Delhi	5,75,762
Mumbai	2,08,174
Calcutta	1,07,500
Madras	1,25,268

The Government has, from 1.4.1995, permitted the registration of only those new four-wheeler petrol vehicles in these four metropolitan cities which have been fitted with catalytic converters and designed to use unleaded petrol. Presently, it is not considered practically feasible or economically viable to retrofit older vehicles with catlytic converters.

(b) The measures being taken and proposed for control of pollution from on-road vehicles include the following:

(i) State Transport Authoriteis enforce the emission standards stipulated for on-road vehicles.

(ii) Lead level is planned to be reduced to a maximum of 0.15 grammes per litre in petrol to be supplied throughout the country by December, 1996.

(iii) Sulphur content in diesel has been reduced to 0.5% in the diesel supplied in the four metropolitan cities of Delhi, Mumbai, Calcutta and Madras from 1.4.1996. It is planned to reduce this further to 0.25% in the diesel supplied throughout the country with effect from 1.4.1999.

(iv) Intensive awareness campaigns have been launched by Transport Departments of cities including Delhi, to educate people about the health effects, measures for maintenance and the statutory punitive provisions related to vehicular pollution.

(v) Steps have been initiated to introduce compressed natural gas in petrol driven vehicles in some of the cities.

Grants to Deemed Universities

*149. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of deemed Universities that are functioning in the country and the names of such deemed Universities, State-wise; and

(b) the number of the deemed Universities which are receiving grants from the UGC and the Central Government for their projects and the amount of grants given to them, University-wise during 1995-96?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): (a) and (b) There are 38 Deemed Universities in the country. The State-wise location of these institutions and the grants released to them during 1995-96 by U.G.C. and Central Government and other bodies is furnished in the statement.

Statement

Statewise details of 38 Deemed Universities alongwith their locations and grants released to each of them during 1995-96.

State	Name of Deemed Universities	Amount of Grant to Deemed Universities by UGC/AICTE/Govt. of India/State Govt. during 1995-96. (Rs. in lakhs)
Andhra Pradesh		
1.	Central Institute of English & Foreign Languages, Hyderabad.	423.28 (UGC)